

सभी औद्योगिक आस्थानों में विकसित की जाएंगी ढांचागत सुविधाएं : सहगल



लखनऊ। अपर मुख्य सचिव, एमएसएमई डॉ. नवनीत सहगल ने कहा कि माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट योजना (एमएसईसीडीपी) के तहत प्रदेश के सभी जिलों में औद्योगिक आस्थानों में ढांचागत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इससे परिवहन सेवाएं बेहतर होगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार का सृजन भी होगा।

सहगल लोक भवन में एमएसईसीडीपी योजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जौनपुर, लखनऊ

और फर्रुखाबाद के औद्योगिक आस्थानों के विकास के लिए भारत सरकार की तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन समिति ने मंजूरी दी है। शीघ्र ही इन जिलों के औद्योगिक आस्थानों में

अपग्रेडेशन का काम शुरू होगा। अन्य सभी जिलों के औद्योगिक आस्थानों के उन्नयन के लिए डीपीआर बनाकर यथाशीघ्र भारत सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अपग्रेडेशन के लिए भारत सरकार 80 प्रतिशत और अधिकतम 10 करोड़ रुपये का अनुदान देती है। ब्यूरो

परि
भा